(8)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
21/4/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.o. 39 R 1&2 CPC सुनी गई। धारा – 212 RT Act r.w.o. 39 R 1&2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिये इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रथम दृष्टया प्रकरण :- आर्थी० प्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम आकोड़िया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी मूल ख० नं० 39 रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा, ख० नं० 40 रकबा 0-15 बीघा व ख० नं० 41 रकबा 4-0 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 34-11 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता प्रताप पुत्र शंकर के खाते दर्ज थी और प्रताप की संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी थी। वादग्रस्त भूमि के प्रताप वल्द शंकर की Ancestral property होने से धारा – 6 Hindu Succession Act के अनुसार प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहित था लेकिन खातेदार प्रताप ने मूल ख० नं० 39 में से अपने हिस्से 1/2 के 2/3 का बेचान अप्रार्थी 2 को वर्ष 2004 में कर दिया था जो अवैध होने से खारिज योग्य है। आर्थी० प्रार्थीगण ने आगे तर्क किया कि प्रताप ने बाद अप्रार्थी 4 गीताबाई को भी रजिस्ट्री करा दी जिसका नामा० दर्ज नहीं हुआ है। आगे तर्क किया कि अप्रार्थी 1 रुपाबाई, प्रताप के भाई गणेश की पुत्री नहीं होने पर गलत [illegible] रिकार्ड में दर्ज करा लिया है। [illegible] माता मगनबाई गणेश को अकेला [illegible] पहले [illegible] चली गई थी अतः उसका भी गणेश [illegible] पर गलत रूप से नाम दर्ज किया गया था जबकि सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म

अत: पैतृक आराजी का खातेदार प्रताप वल्द शंकर द्वारा अप्रार्थी सं० 4 को की गई रजिस्ट्रीयां अवैध व शून्य होने एवं प्रार्थीगण का जन्म से ही हिस्सा निहित होने से प्रताप की भूमि पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

अभि० अप्रार्थी 1 ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुऐ कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता प्रताप के दो अन्य भाई गणेश व देवीलाल थे लेकिन प्रताप ने राजस्व कार्मिको व ग्राम पंचायत के साथ षडयंत्र करके भाई गणेश को लाऔलाद फौत बता कर एवं देवीलाल को वर्षो से लापता (missing) दिखाकर उनके हिस्से 1/3-1/3 पर स्वयं के पक्ष मे विधि विरुद्ध रूप से नामान्तरण दर्ज करा लिया था जिसकी जानकारी मिलते ही गणेश वल्द शंकर के विधिक वारिसान - मगनबाई बैवा व रूपाबाई (पुत्री) ने न्यायालय सहायक कलेक्टर झालावाड के समक्ष वाद सं० 84/464 उनवान मगनबाई बनाम प्रताप दायर किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार अप्रार्थी 1 व माता मगनबाई को खातेदार कृषक घोषित किया गया था और जर्ये नामा० सं० 232 दिनांक 13/02/2001 खातेदार दर्ज हुई थी। प्रार्थीगण या पिता प्रताप ने आज दिनांक उक्त निर्णय की (व नामा० सं० 232) की सक्षम मे न्यायालय मे Appeal पेश नही [illegible] साबित है कि प्रताप व [illegible] ने [illegible] EM Jhaldwar के निर्णय को स्वीकार कर [illegible] था। अप्रार्थी 1 विगत 25-30 वर्षो से रिकार्ड खातेदार व कब्जाधारी है जिसके विरुद्ध बिना किसी आधार के एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रूप से इस न्यायालय ने दिनांक 04/3/2021 को स्थगन जारी कर दिया था जो खारिज योग्य है। अभि० अप्रार्थी 1 द्वारा अपने तर्क किये गया कि मूल खातेदार प्रताप वल्द शंकर, अप्रार्थी 2 रूपाबाई व माता मगनबाई, के मध्य वादग्रस्त भूमि का न्यायालय उपखंड अधिकारी पिडावा के निर्णय व डिक्री से 2005 मे खाता विभाजन होकर पृथक-पृथक खाते दर्ज हो चुकी है। अप्रार्थी 2 पृथक खातेदार व रिकार्डेड खातेदार होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी 1 के पक्ष मे है।

अभि० अप्रार्थी 2 ने प्रार्थीगण की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीया ने रिकार्डेड खातेदार प्रताप वल्द शंकर से पूर्व [illegible] रजि० विक्रय पत्र दिनांक 09/11/2004 से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। अप्रार्थीया विगत 22 वर्षो से लगातार काबिज काश्त होकर तार फैंसिंग कर बर्षो से संतरे का बगीचा लगा रखा है। अप्रार्थीया की sale deed को आज तक किसी भी civil court मे challenge नहीं किया गया है। रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध stay order जारी करना विधि विरुद्ध है। अपने support मे 05 wi[illegible] के शपथ पत्र पेश किये [illegible] की है जो अप्रार्थीया के [illegible] confirm करते है। वादग्रस्त [illegible] पिता की ancestral property नहीं होकर केवल पिता शंकर से प्राप्त व कोर्ट से विभाजित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही [illegible]
	संपति है। अनावश्यक रूप से गैर कानूनी रूप से भिन्न-भिन्न नामो से अविधिक suit दायर कर अवैध स्टे आर्डर ले रखे है जिनसे रिकार्डड खातेदार, सद्‌भावी क्रेता व शांतिपूर्ण कब्जाधारी को उसके विधिक (Legal rights) अधिकारो से वंचित कर अपूरणीय क्षति भी कारित कर रखी है। प्रताप ने अप्रार्थी 4 को भी sale deed से भूमि बेचान कर दी है लेकिन अभी तक mutation दर्ज नहीं होने से प्रताप हिस्सा 1/3 (एक खाते मे) पर सहखातेदार दर्ज है लेकिन ownership नही है। अब प्रार्थीगण व अप्रार्थी 4 मिल गये है।
	आर्मि0 अप्रार्थी 3 ने बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता की पैतृक संपत्ती है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। प्रताप का वादग्रस्त भूमि मे हिस्सा 1/3 निहित था, शेष 2/3 भाग प्रार्थीगण का था लेकिन प्रताप ने पूरी भूमि का बेचान कर दिया जो गलत है। मगनबाई की पुत्री अप्रार्थी 1 ने राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज होने का गलत फायदा उठाकर इस न्यायालय से [illegible] 149/2005 देवीलाल उर्फ दयालचन्द [illegible] बनाम [illegible] मे वर्ष 2005 से ही stay [illegible] भी वर्ष 2019 मे ख0नं0 605/39 का बेचान रामसिंह व राजाराम गुर्जर को किया था जिसका नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
अतः वादग्रस्त भूमि को खुर्द-बुर्द होने एवं अवैध होने से बचाने के लिए राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित है।	
उक्त उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आकोडिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2072-75 के अनुसार खाता सं० 40 ख० नं० 39 रकबा 3.7686 है० प्रार्थीगण के पिता प्रताप हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी सं० 2 मुन्नीबाई 1/3 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है जबकि खाता सं० 199 ख० नं० 40, 41 व 605/39 अप्रार्थी 1 रूपाबाई की पृथक खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थी 1 रिकार्डेड खातेदार कृषक (sole Khatedar tenant) है जबकि अप्रार्थी 2 Recorded co-tenant है। खाता सं० 40 मे से भी मृतक खातेदार प्रताप ने अपना शेष हिस्से 1/3 का बेचान पर्व registered sale deed अप्रार्थी सं० 4 गीताबाई को किया जा चुका है लेकिन नामान्तरण दर्ज नही होने से विक्रेता प्रताप की ही नाम दर्ज है। माननीय supreme court द्वारा अनेक निर्णयो मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "mutation entries do not confer any title." अतः स्पष्ट है कि वर्तमान मे [illegible] के actual ownership [illegible] के पक्ष मे निहित है, ना कि [illegible] मे निहित है।	
प्रार्थीगण के पिता प्रताप द्वारा किये	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

गये बर्षों पुराने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों (registered sale deeds) को किसी सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा खारिज किये जाने का भी कोई साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक आराजी (ancestral property) बताकर मूल अनुतोष के रूप में जन्म से ही हक व अधिकार निहित होना बताया है। यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण हिन्दू है। अताधिक की हिन्दू विधी के अनुसार "चतुर्थ पुरुष पीढ़ी से विरासत मे अविभाजित रूप से प्राप्त संपत्ति पैतृक आराजी मानी गई है"। हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि का विरासत मे संयुक्त रूप से 4th male generation यानी प्रताप के पिता शंकर के दादा जी से प्राप्त होने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। शंकर के फौत होते तीनो पुत्रो प्रताप, गणेश व डेवी को हिस्सा 1/3-1/3 प्राप्त हुई थी। शंकर को यह भूमि कहां से, कैसे (विरासत/दान/विक्रय पत्र etc) प्राप्त हुई? इसका कोई साक्ष्य नहीं है। फिर भाई गणेश (लावल्द फौत बताकर) व डेवीलाल (लापता बताकर) का हिस्सा भी नामान्तरण सं० 54 दिनांक 19/12/1975 से प्रताप के खाते दर्ज कर दिया गया था। [illegible] द्वारा पेश ACM court झालावाड़ के निर्णय [illegible] से जाहिर है कि [illegible] 088 [illegible] अवयस्क [illegible] (बेवा) व रूपाबाई (पुत्री) को मृतक गणेश वल्द शंकर का वारिसान मानते हुए न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि किता 3 रकबा 34-11 बीघा मे हिस्सा 1/2 पर खातेदार घोषित किया था (प्रकरण सं० 464/.. [illegible]

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

मगन बाई वगै० बनाम प्रताप वगै० u/s 88, 91, 53, 183 RT Act) घोषित किया था और फिर नामा० सं० 232 दिनांक 13/02/2001 से सहखातेदार दर्ज हुई थी। प्रार्थीगण द्वारा पेश जमाबंदी संवत 2060-63 के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी, पिडावा के निर्णय व डिक्री की पालना मे दर्ज नामान्तरण सं० 472 दिनांक 07/01/2005 से प्रताप, मुन्नीबी (अप्रार्थी 2) एवं कमलाबाई व मगनबाई के मध्य बटवारा होकर भूमि पृथक-पृथक खाते दर्ज हुई थी अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि ना तो 4th male generation से प्राप्त हुई है और खाता विभाजन होने से शामलाती (संयुक्त परिवार की सम्पत्ति) का गुण भी समाप्त हो गया है और इसलिए ancestral property साबित नहीं है।

The Hindu Succession Act 1956 की धारा-6 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी संपत्ति मे प्रत्येक सहदायिक का जन्म से हक व अधिकार (Notional share u/s 20) निहित होता है (under the Mitakshara school of Hindu law, Co-parcenary property is ancestral property shared among co-parceners by birth from 4th male generations). मिताक्षरा हिन्दू विधी मे केवल एक male ही co-parcener हो सकता था 2005 मे The Hindu Succession Act मे संशोधन कर daughter (female) को भी co-parcener माना गया है।

A Co-parcener gets the rights to co-parcenary property (ancestral property) from the moment he

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

8.

is born, his/her interest is equal to his father and the Karta (कर्ता) of the Hindu Joint family can not alienated (sell or transfer or any other deal) in a way that denies him from the Hindu joint family property.

हिन्दू उत्तराधिकार की मिताक्षरा विधि के अनुसार– "A co-parcener has the right to ask for partition without the father's consent. A co-parcener can not transfer the property in favour of one co-parcener but has to renounce the property so that it can be equally divided among the remaining co-parceners."

अतः स्पष्ट है कि "Senior most male member with lineal male descendants (an ancestor through his son, grandsons, great-grand sons and so on) till 4th male generations including him will form a coparcenary." हस्तगत प्रकरण में ग्राम आकोडिया की वादग्रस्त भूमि ख०न० 39, 605/39, 40 व 41 किता 4 कुल रकबा 34-11 बीघा भूमि senior most male Khatedar मृतक शंकर से विरासत (केवल) में प्रताप, गणेश व डेवीलाल को 1/3-1/3 प्राप्त होकर न्यायालय ACEM Jhalawar के निर्णय दिनांक 26/08/1988 से प्रताप एवं गणेश के LRs (मगनबाई + रूपाबाई) के हिस्से 1/2-1/2 दर्ज हुई है अर्थात केवल एक पुरुष पीढ़ी से (one male generation) [illegible] से शामलाती आकर फिर न्यायालय उपखण्ड [illegible] पिडावा के निर्णय व डिक्री [illegible] प्रताप, रूपाबाई व अन्य के मध्य खाता विभाजन (बटवारा) होकर नामा० 472 Dt 07/01/2005 से पृथक-पृथक खाते दर्ज हुई थी परिणामतः वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
Hindu joint family की सयुंक्त संपत्ति (joint property) नहीं होकर मृतक प्रताप व अप्रार्थी 1 की (divided and seperate property) पृथक व विभाजित संपति है अर्थात यह सयुंक्त हिन्दू परिवार की सयुक्त सहदायिकी संपति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से साबित है कि वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 34-11 बीघा मृतक प्रताप की (हिस्सा 1/3) विरासत की संपति (inherited property) तो है लेकिन ancestral property (पैतृक आराजी) नहीं है।	

माननीय supreme court ने विभिन्न निर्णयों मे अभिनिर्धारित किया है कि "The property loses its ancestral charactor and become self-acquired property in cases where the ancestral property has been partitioned".

Angadi chandranna v/s shankar (April 2025) मामले मे भी हाल मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "After a formal joint family property partition, each share automatically becomes self-acquired for the allottee, granting full freedom to sell, gift or transfer indendently."

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम आकोदिया की [illegible] खातेदार प्रताप वल्द शंकर [illegible] से ही प्राप्त व विभाजित (divided) [illegible] तथा ACEM Jhalawar के निर्णय Dt [illegible]/8/1988 को किसी अपीलीय कोर्ट द्वारा खारिज नहीं करने के आधार पर और रजि० विक्रयपत्रों के मूल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

भूमि का बैचान अप्रार्थी 2 व 4 को किये जाने (रिकॉर्ड खातेदार कृषक) से प्रकरण प्रथम दूसरा प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होकर अप्रार्थीगण 1, 2 व 4 के पक्ष मे साबित

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण प्रथम दूसरा प्रार्थीगण के ~~पक्ष~~ विरुद्ध साबित है। वादग्रस्त भूमि मृतक प्रताप मे केवल inherited property होकर ancestral property साबित नही होने, अप्रार्थी 1 व 2 के रिकॉर्ड खातेदार कृषक होकर पृथक खाते दर्ज होने, भूमि के सह खातेदारो के मध्य 2005 मे SDO court से बंटवारा (Partition) होने और रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को competent civil court से आज तक खारिज नही करने से प्रार्थीगण के पक्ष मे स्थगन जारी करने से अप्रार्थी 1, 2, 4 को अत्याधिक असुविधा (severe inconvenience) कारित हो रहा है और होगा। रिकॉर्ड खातेदारो को अकारण ही अपने खातेदारी एवं अन्य कानूनी अधिकारो से वंचित कर रखा है। गवाहो के बयानो व बहस से यह भी जाहिर है कि अप्रार्थी 2 मुन्नी बी वर्ष 2004 से कब्जशुदा आराजी पर काबिज काश्त होकर संतरे का बगीचा लगातार तार फेंसिंग कर रखा है। [illegible] मानकर प्रथम के पक्ष मे [illegible] / नामा० क्र० 54 Dt [illegible], द्वारा [illegible] मे अपने प्रभाव 450 [illegible] मे स्वयं के लिए कोई अनुतोष क्लेम नही किया है, केवल प्रार्थीगण के claim का ही support किया है। प्रताप द्वारा बेचान शुदा (स्वअर्जित भूमि) भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

पुत्री - प्रार्थीगण का अब कोई हक व अधिकार शेष नहीं बचा है फिर भी प्रार्थीगण के पक्ष मे दिनांक 04/09/2021 को अन्तरिम (interim stay) अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जो वर्तमान में कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थीगण के पक्ष से स्थगन जारी करने से हक और अप्रार्थी 1 व 2 को स्वयं की रिकार्ड खातेदारी के अधिकारों व अन्य कानूनी अधिकारों से वंचित किया जायेगा, बल्कि वाद-बहुलता (multiplicity of suits) भी बढ़ायेगा। अप्रार्थीगण को (अपेक्षाकृत) अत्यधिक नुकसान भी कारित करेगा। अप्रार्थी 1, 2 व 4 को भूमि विकास, भू-सुधार, कृषि ऋण, अन्य सरकारी सहायताओं, कृषि कार्य आदि से भी वंचित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करना ही होगा।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में सुविधा का सतुंलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं होकर अप्रार्थी 1, 2 व 4 के पक्ष मे साबित है।

(स) अपूरणीय क्षति :- प्रार्थीगण के पक्ष से प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का सतुंलन नहीं होने पर भी स्थगन जारी कर अप्रार्थीगण को (जो कि रिकार्ड खातेदार कृषक है) को खातेदारी अधिकार, [illegible] व विकास के अधिकार, कृषि ऋण, अन्य सरकारी सहायताओं के अधिकार, [illegible] कानूनी अधिकारों से रोकने पर अप्रार्थीगण को ही अपूरणीय क्षति कारित होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.o. 39 R1&2 CPC खारिज (dismiss) किया जाता है। प्रार्थिया के पक्ष में पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।
	/04/2026 उपखण्ड अधिकारी जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner